



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 06 पटना, बुधवार, 18 माघ 1939 (श0)
7 फरवरी 2018 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	4-5	
पूरक	---	
पूरक-क	6-9	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी 2018

सं० ई2-2-036/2010-51—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री प्रशांत शेखर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु०), निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को चेन्नई एवं तिरुपति यात्रा के निमित्त दिनांक 01.11.2017 से 17.11.2017 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 18.11.2017 एवं 19.11.2017 को शनिवारीय-रविवारीय अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति दी जाती है।

आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

29 जनवरी 2018

सं० 15/एम 1-160/2014-124—बिहार राज्य के वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर में निजी क्षेत्र में डॉ० सी०वी रमण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT) से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्यांकन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 द्वारा इस विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 2 (2) के तहत आशय पत्र की समयावधि को दो वर्षों के लिए अधिकतम विस्तारित किया गया है।

विभागीय स्तर से निर्गत उक्त आशय पत्र के आलोक में प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रदत्त अधिकार के तहत प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), SCOPE Campus, NH-12, Bhaironpur, (Near misrod) hosangabad road, Bhopal-462026 को “डॉ० सी०वी रमण विश्वविद्यालय” के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं भगवानपुर (वैशाली) में पटना साहिब एजुकेशनल ट्रस्ट से किराएनामा किए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

दो वर्षों के उपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के धारा 5 (1) (iii) के तहत विश्वविद्यालय के लिए स्थायी भवन निर्मित नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 एवं पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्गत आशय पत्र एवं इस अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय स्थापना/औपबधिक संचालन हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

यह विश्वविद्यालय डॉ० सी०वी रमण विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

30 जनवरी 2018

सं० 6/प्रो०—06—002/94(खण्ड)—281(अनु०)/वा०कर—सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या—5463/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त वाणिज्य—कर उपायुक्त को वाणिज्य—कर उपायुक्त कोटि (वेतनमान् रु० 12000-375-16500) से वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान् रु० 14300-400-18300) कोटि में दिनांक 11.12.2008 से वैचारिक तथा दिनांक 12.01.2009 से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि

अधीक्षक का कार्यालय, प्रेस एवं फॉर्म्स, गया

पुनर्निविदा सूचना-2

23 जनवरी 2018

सं० 600/प्र०—प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में निम्नलिखित रद्दी कागज एवं एल्युमिनियम प्लेट जैसा जहाँ है के आधार पर बिक्री हेतु मुहर बंद निविदा दिनांक 23.02.2018 को 2:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा दिनांक 24.02.2018 को 12:00 बजे उपस्थित क्रय समिति के सदस्यों/निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी। निविदा दिनांक 23.02.2018 को 2:00 बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

बिक्री की जाने वाले रद्दी कागजों का विवरण अनुमोदित मात्रा एवं पूर्व न्यूनतम बिक्री दर निम्नवत है।

रद्दी कागजों का विवरण	मात्रा	न्यूनतम निर्धारित दर
1. रील अंत कोर के साथ बचा हुआ कागज	— 05 M.T	22.00
2. रील से निकाला गया सादा रद्दी कागज	— 05 M.T	26.00
3. मिले-जुले रद्दी कागज, मलाट स्वीपिंग आदि	— 15 M.T	05.00
4. कतरण	— 20 M.T	10.00
5. रद्दी अल्युमिनियम प्लेट	— 200 KG	100.00

निविदा की शर्तें

1. निविदादाताओं को निविदा के साथ 50,000(पचास हजार) रुपया का राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र (आठवाँ निर्गम), बैंक ड्राफ्ट, जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा। जो अधीक्षक, प्रेस एवं फॉर्म्स, गया के नाम से प्लेज किया हुआ हो।
2. उपर्युक्त सामग्रियों "जहाँ है जैसा है" उसी रूप में अधिकतम दर देने वाले निविदादाता को ले जाना होगा।
3. इच्छुक व्यक्ति निविदा के पूर्व किसी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर उपर्युक्त सामग्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. निविदादाताओं को सामग्रियों का इकाई बार अधिकतम मूल्य प्रति किलो में देना होगा। जिस सामग्रियों में उनके द्वारा अपने निविदा में दर अभिव्यक्त नहीं किया होगा उस सामग्री के लिए उन्हें वंचित कर दिया जायेगा।
5. सफल निविदादाताओं को सामग्रियों के पूर्ण भुगतान करने के बाद ही उन्हें सामग्रियों की विमुक्ति की जायेगी।
6. निविदादाताओं को आयकर एवं बिक्री कर से निबंधन होना अनिवार्य होगा तथा निविदा में संबंधित भुगतान किये गये रकम के विरुद्ध आयकर/बिक्रीकर जी०एस०टी० एवं अन्य कर का भुगतान वे स्वयं करने हेतु जिम्मेवार होंगे।

7. सफल निविदादाताओं द्वारा उच्चतम दर की स्वीकृति के पश्चात् उनके द्वारा या निर्धारित अवधि तक राशि जमा कर संबंधित सामग्रियों का उठाव नहीं कर लिया जाता है तो उनके द्वारा दाखिल जमानत की राशि जब्त कर लिया जायेगा। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत अथवा रद्द कर सकते हैं।
9. विलंब से प्राप्त निविदा आमंत्रण पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. यदि इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर करना आवश्यक हुआ तो वह गया के अदालत में होगा।

आदेश से,
अरुण कुमार सिंह, अधीक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 एल/एच०जी०- 2006/2015-726

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

25 जनवरी 2018

समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, पटना के पत्रांक-3854, दिनांक 28.09.2015 के द्वारा श्री आमिर इसरार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नवादा, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं कमजोर कार्यालय नियंत्रण से संबंधित आरोप प्रपत्र-‘क’ में विभाग को प्राप्त हुआ।

2. प्राप्त आरोप प्रस्ताव पर श्री इसरार के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए उनसे बचाव अभिकथन की मांग विभागीय पत्रांक-636, दिनांक 24.01.2017 द्वारा की गई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना बचाव अभिकथन विभाग में अपने कार्यालय के पत्रांक-259, दिनांक 25.02.2017 द्वारा समर्पित किया गया।

3. प्राप्त बचाव अभिकथन पर महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग विभागीय पत्रांक-4666, दिनांक 26.05.2017 द्वारा की गई। बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना के पत्रांक-3337, दिनांक 05.09.2017 द्वारा महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के मंतव्य से अवगत कराया गया, जिसमें दोनों कंडिकाओं में अपचारी के विरुद्ध गठित आरोपों के संबंध में प्राप्त बचाव अभिकथन संतोषजनक बताया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक-9866, दिनांक 16.11.2017 के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना के पत्रांक-4846, दिनांक 12.12.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दो कंडिकाओं में गठित आरोप प्रपत्र ‘क’ के विरुद्ध समर्पित बचाव अभिकथन पर कंडिकावार समीक्षा/मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें बचाव अभिकथन संतोषजनक बताया गया है।

4. वर्णित स्थिति में श्री आमिर इसरार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नवादा, सम्प्रति बेगूसराय के द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन को स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ की कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

सं० 5 नि०गो०वि०(5) 15/2014 (खण्ड) —28 नि०गो०

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

1 फरवरी 2018

वर्ष 2003 से 2007 एवं 01 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2008 तक पशु रक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम में दवा क्रय में हुयी वित्तीय अनियमितता के लिए डॉ० दिलीप कुमार झा, तत्कालीन पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध सरकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम—139(ग) के तहत कार्यवाही करते हुये विभागीय संकल्प 142 नि०गो०, दिनांक 07.06.2016 द्वारा डॉ० झा का पूर्ण पेंशन रोका गया।

2. उक्त विभागीय संकल्प के विरुद्ध डॉ० झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 12155/16 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 12.12.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के द्वारा पारित न्याय निर्णय में डॉ० झा को पूर्ण पेंशन (बकाया सहित) भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया।

3. उक्त न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी और समीक्षोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के अनुपालन में डॉ० झा का पूर्ण पेंशन (बकाया सहित) मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ० दिलीप कुमार झा, तत्कालीन पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विभागीय संकल्प 142 नि०गो०, दिनांक 07.06.2016 द्वारा जब्त किये गये पूर्ण पेंशन (बकाया सहित) को मुक्त किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

सं० कारा/नि०को०(विविध)—10—14/2015—655

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

30 जनवरी 2018

श्री प्रताप नारायण सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई सम्प्रति उप महानिरीक्षक (सुधार), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के विरुद्ध उनके मंडल कारा, जमुई में पदस्थापन काल में बंदी नरेश यादव की इलाज में लापरवाही के फलस्वरूप दिनांक 11.04.2010 को सदर अस्पताल, जमुई में इलाज के दौरान हुई मृत्यु की घटना में बरती गई लापरवाही, कर्तव्योपेक्षा एवं प्रशासनिक विफलता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 888 दिनांक 09.02.2016 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 327 अनु0 दिनांक 28.07.2017 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 5043 दिनांक 06.09.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री सिंह ने अपने पत्रांक 6398 दिनांक 09.11.2017 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि किसी भी बंदी को कारा में प्रवेश कराने का दायित्व कारा हस्तक के नियमानुसार कारापाल, सहायक कारापाल अथवा अपराहन ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी का है, न कि काराधीक्षक का। मृत बंदी नरेश यादव दिनांक 03.04.2010 को अपराहन 4:10 बजे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई के द्वारा निर्गत अभिरक्षा प्रपत्र के आधार पर कारा में प्रवेश पाया था। अभिरक्षा प्रपत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा उसके शारीरिक चोट या इलाज से संबंधित किसी प्रकार का निर्देश अंकित नहीं था जिसके कारण उन्हें अथवा कारा प्रशासन के किसी पदाधिकारी को बंदी नरेश यादव के रिमांड के पूर्व गंभीर रूप से घायल रहने की सूचना नहीं थी। प्रवेश के समय चिकित्सा कर्मी द्वारा पूछताछ में बदन दर्द करने की मात्र जानकारी दी गयी, जिसके लिये उसे दर्द निवारक दवाई मात्र दी गयी। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि साक्ष्य रूप में प्रवेश पंजी मात्र के अवलोकन से स्पष्ट हो जाएगा कि वे दिनांक 03.04.2010 से 11.04.2010 के बीच 05 तिथियों में कारा के अंदर गये हैं। नियमानुसार अधीक्षक अपनी अनुपस्थिति की जानकारी मिनटबुक के माध्यम से ही कारापाल को देते हैं। मिनट बुक नहीं रहने तथा 6-7 वर्ष का समय बीत जाने के कारण अपनी अनुपस्थिति की तिथियों के संबंध में सही-सही जानकारी देना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप को मिथ्या बताया है कि वे दिनांक 03.04.2010 से दिनांक 11.04.2010 तक की अवधि में कारा के अंदर नहीं गये। जवाब के अनुसार उसी प्रवेश पंजी के आधार पर अन्य पदाधिकारियों यथा कारापाल तथा सहायक कारापाल को कारा के भीतर जाने-आने को सही माना जा रहा है तथा उसी प्रवेश पंजी में उनके आने-जाने की प्रविष्टि को सही नहीं मानकर आरोप लगाया जा रहा है जो अन्यायपूर्ण है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा कारा हस्तक के नियमों का सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों से अनुपालन करवाया गया है। बंदी नरेश यादव का कारा प्रवेश नियमानुसार कारापाल के द्वारा कराया गया है। प्रवेश के उपरांत वहां मौजूद **Medical Subordinate** के द्वारा बंदी की जॉच कारापाल के निर्देश पर करायी गयी है। बाद में कारा के मेडिकल ऑफिसर द्वारा भी उसी तिथि को बंदी नरेश यादव का शारीरिक जांच किया गया तथा दवाई भी दी गयी। उनका कहना है कि जहाँ तक चिकित्सक द्वारा बंदी के शरीर का पूर्ण जांच नहीं किये जाने का प्रश्न है, वास्तव में यह उनकी लापरवाही और कार्य में उनकी उदासीनता है, न कि उनके अथवा कारा प्रशासन का।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा कारा हस्तक नियमों का उल्लेख करते हुए यह कहना कि कारा में बंदियों को प्रवेश लेने की प्राथमिक जिम्मेवारी कारापाल की होती है न कि काराधीक्षक की तथा चिकित्सा के मामले में कारा अधीक्षक का चिकित्सक के उपर कोई नियंत्रण नहीं है। बंदी नरेश यादव का पूर्ण शारीरिक जांच दिनांक 03.04.2010 को नहीं किये जाने के लिए कारा अधीक्षक जवाबदेह नहीं है, उनका यह कहना उनकी कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का द्योतक है, क्योंकि कारा हस्तक के नियम 60 एवं 61 के प्रावधानों के तहत काराधीक्षक संपूर्ण कारा के नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होते हैं। आरोपित पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि वे दिनांक 03.04.2010 को 2:30 बजे तक कारा कार्यालय में उपस्थित रहे हैं। बंदी नरेश यादव का कारा गेट पंजी के अनुसार कारा में प्रवेश अपराहन 04:10 बजे हुआ है। संयुक्त जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 03.04.2010 से दिनांक 11.04.2010 तक उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक प्रतिदिन कारा में जाते रहे हैं, परन्तु संबंधित अभिलेखों में काराधीक्षक द्वारा कारा के अंदर जाने का उल्लेख नहीं

पाया गया है। आरोपित पदाधिकारी ने अपने बचाव में कुछ नहीं लिख कर सिर्फ कारा हस्तक नियम का उल्लेख करते हुए कहा है कि बंदी प्रवेश में अधीक्षक की कोई जवाबदेही नहीं है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार काराधीक्षक की लापरवाही के कारण ही बंदी नरेश यादव की मृत्यु हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी आदेश दिया है वह इसी मृत्यु से जनित परिणाम है। उनके द्वारा अपने बचाव के पक्ष में कुछ न कह कर सिर्फ जवाबदेही से बचने का प्रयास मात्र किया गया है। अतः उनका द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार्य करने योग्य नहीं है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :-

“ वर्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से दो वेतनवृद्धि घटाकर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर पड़ेगा ”।

6. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2599 दिनांक 25.01.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रताप नारायण सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई, सम्प्रति उप महानिरीक्षक (सुधार), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

“ वर्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से दो वेतनवृद्धि घटाकर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर पड़ेगा ”।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>